स्थापना : 1997 संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -14 ■ अंक - 140 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 सितंबर 2015 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

भा.रे. की स्थिति आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी है -रेलमंत्री

■ आईसीयू में भर्ती किसी मरीज से चीनी रेलवे के साथ मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती

■ क्षमता के अनुरूप भारतीय रेल को ढुलाई के लिए नहीं मिल रहा है पर्याप्त माल -सुरेश प्रभु

कोलकाता : रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने 'भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स' की ओर से यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय रेल को ढुलाई के लिए पर्याप्त माल नहीं मिल रहा है, जबकि इसकी क्षमता सालाना 1.2 अरब टन माल ढुलाई की है. हालांकि यह समस्या रेलवे क्षेत्र से बाहर का मुद्दा है, लेकिन फिर भी अगर रेलवे को पर्याप्त मात्रा में माल ढुलाई के लिए मिले, तो इससे रेलवे को काफी आमदनी हो सकती है. श्री प्रभु ने कहा कि रेलवे प्रत्येक वर्ष 1.2 अरब टन माल ढुलाई करने की तैयारी में हैं. इस संबंध में उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बताया है कि रेलवे और ज्यादा कोयले की ढुलाई कर सकती है, लेकिन रेलवे को ढुलाई के लिए क्षमता के मुताबिक पूरा माल नहीं मिल रहा है. रेलमंत्री ने कहा कि इसलिए यदि हमें और कार्गो मिलता है, तो हमें ज्यादा खुशी होगी. अगला कार्य सत्र, जो मुख्य रूप शेष पेज 7 पर...

चार साल बाद मिला मेट्रो रेलवे को अपना महाप्रबंधक

अश्वनी कपूर को बनाया गया मेट्रो रेलवे का नया जीएम

कोलकाता. काफी जद्दोजहद के बाद आखिर अश्वनी कुमार कपूर को मेट्रो रेलवे, कोलकाता का नया महाप्रबंधक बना दिया गया है. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) जी. आर. अग्रवाल ने श्री कपूर का नियुक्ति आदेश बुधवार, 26 अगस्त को जारी कर दिया. श्री कपूर ने अपना नया पदभार तत्काल प्रभाव से ग्रहण कर लिया है. इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (आईआरएसईई) के वर्ष 1979 बैच के वरिष्ठ रेल अधिकारी श्री कपूर वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में मुख्य शेष पेज 7 पर...

अपनी खाल बचाने हेतु रेलवे बोर्ड ने उठाया श्रीधरन की क्षमता पर सवाल

■ श्रीधरन अदालत में देंगे रेलवे बोर्ड द्वारा उठाए गए बचकाने सवालों का जवाब

■ जिस व्यक्ति को 'भारत रत्न' दिया जाना चाहिए, उसकी क्षमता पर रेलवे की नई पीढ़ी की नामुराद औलादों ने लगाया प्रश्नचिन्ह

दिल्ली : अत्यंत विषम स्थितियों में दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे का निर्माण करने में महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाने वाले ई. श्रीधरन की क्षमता और अनुभव पर रेलवे बोर्ड ने सवाल उठाया है. जिस व्यक्ति को 'भारत रत्न' दिया जाना चाहिए, उसकी क्षमता पर रेलवे की नई पीढ़ी की नामुराद औलादों ने यह सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल एक जवाबी हलफनामे में उठाया है. यह मामला जम्मू-कश्मीर में बिछाई जा रही एक रेलवे लाइन की सेफ्टी से जुड़ा है. कश्मीर में रेल लाइन बिछाने में शेष पेज 7 पर...

अवैध रेलवे क्रासिंग बंद करने के प्रति कब सचेत होगा रेल प्रशासन?

■ राजेंद्रनगर टर्मिनल पर पटरी पार करते तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत

■ 'रेलवे समाचार' ने करीब दो साल पहले ऐसे ही किसी भीषण हादसे की पूर्व चेतावनी दी थी

पटना : 'रेलवे समाचार' द्वारा करीब दो साल पहले दिए गए सुझाव पर यदि पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक अमल किया होता, तो बुधवार, 26 अगस्त की शाम करीब 9 बजे राजेंद्रनगर टर्मिनल के पास घटी भीषण दुर्घटना नहीं हुई होती. मगर जनवरी-फरवरी 2014 में जब शेष पेज 7 पर...

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट चार महीने आगे खिसकी

केंद्रीय कर्मचारियों में भारी असंतोष

23 नवं. की प्रस्तावित श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने की तारीख आगे खिसकाई

दिल्ली : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की जो रिपोर्ट 31 अगस्त तक सरकार को सौंपी जानी थी, अब 31 दिसंबर तक के लिए आगे खिसक गई है. इससे तमाम रेल कर्मचारियों सहित लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में एक प्रकार की निराशा का भाव पैदा हुआ है. जबकि कई श्रमिक संगठनों ने अब इस वेतन आयोग की रिपोर्ट के 1 जनवरी 2016 से न लागू हो पाने के प्रति भी आशंका जताई है. सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने की ही राह देख रहे हजारों केंद्रीय कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पूर्व योजना बना रखी है. हालांकि उन्हें यह भी आशा है कि वेतन आयोग द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाए जाने की भी सिफारिश की जा सकती है. कई शेष पेज 7 पर...

रेलवे को राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति का साधन माना जाता रहा है –मनोज सिन्हा

पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह संपन्न

रतलाम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि रेलवे के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा और आगामी पांच वर्षों में रेलवे में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश किया जाएगा. यह बात एक बार फिर से रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने यहां दोहराई है. श्री सिन्हा रविवार, 23 अगस्त को यहां पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक रेलवे को राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति का साधन माना जाता रहा है. यही कारण रहा है कि रेलवे में पर्याप्त निवेश पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया.

रेल राज्यमंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ही रेलवे में 1.10 लाख करोड रुपए का निवेश किया जा रहा है. कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलौत, मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, उज्जैन के सांसद डॉ. चिंतामणि मालवीय, देवास के सांसद मनोहर उंटवाल और पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी सहित जिले के सभी विधायक भी उपस्थित थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल राज्य मंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक रेलवे की यात्री संख्या में सत्रह गुना वृद्धि हुई है, जबकि मालभाड़ा आठ गुना बढ़ा है. इसके बावजूद रेलवे की आधारभूत सुविधाओं में मात्र ढ़ाई प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

उन्होंने पुरजोर लहजे में कहा कि रेलवे को अब तक राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति का साधन माना जाता रहा है. इसलिए हर बजट में नई रेलगाड़ियों को चलाने और उनके ठहराव बनाने को ही प्रमुखता दी जाती रही थी. लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि इस परंपरा को बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि रेलवे की हालत भाषणों से नहीं सुधरेगी. रेलवे की समस्याओं की जड़ निवेश का अभाव है. इसलिए अब सरकार ने तय किया है कि नई ट्रेन और ठहराव की मांगों को छोड़ते हुए रेलवे में निवेश को बढ़ाया जाएगा. आगामी पांच वर्षों में रेलवे में 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. जबकि चालू वर्ष में रेलवे में 1.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है. यह भी निर्णय लिया गया है कि देशहित में पहले पुरानी और अधूरी पड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा.

भारतीय रेलवे मजदूर संघ और उससे सम्बद्ध पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद जैसे सभी जोनल संगठनों को मान्यता दिए जाने की मांग पर श्री सिन्हा ने कहा कि इसे तीसरे नंबर का नहीं, बल्कि पहले नंबर का संगठन बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संगठन के पदाधिकारियों/सदस्यों को अब उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि रेलवे एक असैन्य सैनिक संगठन है, जिसके 13 लाख से अधिक कर्मचारी बिना कोई अवकाश लिए प्रत्येक तीज-त्यौहार पर गाड़ियां चलाते हैं और हर मौसम में रात-दिन लगातार ट्रैक का निरीक्षण करते हैं.

उन्होंने कहा कि रेलवे की ख्याति रेल अधिकारियों अथवा मंत्रियों की वजह से नहीं है, बल्कि इसके 13 लाख रेल कर्मचारियों की वजह से है. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलौत ने रेल राज्यमंत्री से उज्जैन-आगर रेल लाइन का सर्वे पुनः शुरू किए जाने की मांग की. इस अवसर पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष मंगेश देशपांडे ने भी पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया.

रेलवे को अपने मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए -डॉ. डी. पी. पांडेय

रतलाम : रेलवे को अपने मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहिए. रेलवे अस्पतालों में वर्तमान में डॉक्टरों की कमी के कारण कई समस्याएं आ रही हैं. रेलवे के अपने मेडिकल कॉलेज होने से इस समस्या का समाधान हो सकता है. यह सुझाव यहां रेलवे अस्पताल में आयोजित दो दिवसीय रेलवे फोरम ऑफ एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के 21वें वार्षिक सम्मेलन के समापन अवसर पर पश्चिम रेलवे के मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. डी. पी. पांडेय ने दिया है. सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए निश्चेतना विशेषज्ञों ने निश्चेतना विज्ञान से संबंधित अलग-अलग विषयों पर अपने व्याख्यान दिए. सम्मेलन में उपस्थित निश्चेतना विशेषज्ञों ने डॉक्टरों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए.

एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के इस वार्षिक सम्मेलन में भारतीय रेल के विभिन्न जोनों से 35 से अधिक निश्चेतना विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हुए. इंदौर स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉ. इदरीस खान एवं डॉ. राजेश भराणी ने हृदय रोग के संबंध में और चौथराम हॉस्पिटल के डॉ. काठेड़, मोहक अस्पताल के डॉक्टरों ने एनेस्थिसिया देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की. मंडल रेल चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ए. के. मालवीया ने वीडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से अलग-अलग विषयों पर विचार व्यक्त किए. सम्मलेन के समापन पर मंडल रेलवे अस्पताल के डॉ. राजीव दशोत्तर ने सभी उपस्थितों के प्रति आभार व्यक्त किया.

'रामचरित मानस में वैज्ञानिक दृष्टि' विषय पर डॉ. आर.आर.उपाध्याय का व्याख्यान

कल्याण : 'अखिल भारतीय साहित्य परिषद' द्वारा 23 अगस्त को रेलवे ऑफिसर्स क्लब, कल्याण में 'रामचरित मानस में वैज्ञानिक दृष्टि' विषय पर डॉ. आर. आर. उपाध्याय के सारगर्भित व्याख्यान का आयोजन किया गया. मेडिकल पेशे से जुड़े और कल्याण में दो बड़े अस्पतालों के संचालक डॉ. उपाध्याय ने इसी विषय पर मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट (पीएचडी) की उपाधि ग्रहण की है. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ही मेडिकल में एमडी और कानून में एलएलबी की भी डिग्री हासिल की है. इस अवसर पर डॉ. उपाध्याय के साथ मंच पर 'रेलवे समाचार' के संपादक सुरेश त्रिपाठी और श्री उपाध्याय विराजमान थे.

बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ. उपाध्याय ने रामचरित मानस के प्रमुख पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहित उनके अन्य तीनों भाईयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म सहित कई संदर्भों का मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से दो घंटे तक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि वस्तुतः एक फल को आधा और फिर आधे को आधा तीन भाग करके तीनों रानियों को खिला देने से रामायण के प्रमुख पात्रों की पैदाईश नहीं हुई है, बल्कि जिस यज्ञ का उल्लेख किया गया है, वह वास्तव में ऋषि की प्रयोगशाला है, जिसमें पूरी वैज्ञानिक पद्धति से निषेचन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया. उन्होंने स्त्री एवं पुरुष क्रोमोसोम की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए वर्तमान टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से जोड़कर इसका पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया. उन्होंने यह भी कहा कि तब का हमारा विज्ञान बहुत उन्नत था. हमारे ऋषि-मुनि तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके सिर्फ गुरुकुल ही नहीं चलाते थे, बल्कि वे उच्चकोटि के वैज्ञानिक भी थे.इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री डॉ. दिनेश सिंह एवं संजय द्विवेदी ने प्रारंभ में रामचरित मानस के धार्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला. इस आयोजन की व्यवस्था सुरेंद्र शर्मा ने की थी. इस सत्संग के मौके पर निर्माण व्यवसायी एवं भाजपा पदाधिकारी करुणाशंकर शुक्ला, सत्यनारायण दुबे सहित बड़ी संख्या में सुधि श्रोतागण उपस्थित थे.

'जीवन जीने की कला एवं राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन'

कोलकाता : मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा हाल ही में 'जीवन जीने की कला एवं राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन' विषय पर तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्य राजभाषा अधिकारी परसुराम सिंह ने मेट्रो रेलवे में राजभाषा के कामकाज और प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों और रेलकर्मियों से राजभाषा में अपना दैनंदिन कामकाज करने का आहवान किया.

कार्यक्रम का संचालन करते हुए उप महाप्रबंधक/राजभाषा डॉ. बरुण कुमार ने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला और इस संदर्भ में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी. 'जीवन जीने की कला' विषय पर सहायक सुरक्षा आयुक्त/अग्नि ने पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जीवन जीने की कला पर व्यापक चर्चा की. तत्पश्चात डॉ. बरुण कुमार ने उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों और कर्मचारियों से हिंदी में अधिकाधिक काम करने की अपील करते हुए सभी का धन्यवाद किया.

उत्तर रेलवे की सीनियर डीएसटीई कांफ्रेंस संपन्न

दिल्ली : उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार अभियंताओं (सीनियर डीएसटीई) की कांफ्रेंस का आयोजन 19 अगस्त को उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस में किया गया. कांफ्रेंस का आयोजन मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार अभियंता (सीएसटीई) द्वारा किया गया. इस मौके पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. पुठिया ने कांफ्रेंस में उपस्थित उत्तर रेलवे के सभी मंडलों से आए सीनियर डीएसटीई को सम्बोधित किया. महाप्रबंधक ने सिगनल एवं दूरसंचार गियरों के सुरक्षित एवं विश्वसनीय कार्य प्रणाली पर विशेष बल दिया. उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीनियर डीएसटीई को निर्देश दिया. बैठक को उत्तर रेलवे के अन्य विभाग प्रमुखों ने भी सम्बोधित किया.

तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए सुरेश त्रिपाठी का राजस्व मंत्री खड़से के हाथों सम्मान

भुसावल : ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' के संपादक सुरेश त्रिपाठी को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. यह सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह भुसावल मंडल, मध्य रेलवे के कृष्णचंद्र रेलवे सभागार में 'मानवसेवा व पर्यावरण बचाव फाउंडेशन' की तरफ से रविवार, 16 अगस्त को आयोजित किया गया था. इस अवसर पर राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के साथ मंच पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद हुसेन खान आमिर साहब, पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक हरिभाऊ जावले, विधायक संजय सावकारे और प्रा. सुनील नेवे आदि गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे.

इस अवसर पर भुसावल जिले के पालक मंत्री एवं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने सभागृह में बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण आज विश्व को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यह स्थिति भविष्य में समस्त मानवजाति के विनाश का कारण बन सकती है. इसलिए पर्यावरण संवर्धन समय की आवश्यकता है. इसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयत्न करना चाहिए. श्री खड़से ने कहा कि मानवसेवा व पर्यावरण बचाव फाउंडेशन की तरफ से मरीजों और उनकी तीमारदारी करने वाले उनके नाते-रिश्तेदारों के लिए भोजन की मुफ्त व्यवस्था करने के साथ ही पर्यावरण के बचाव के लिए किया जा रहा प्रयास अत्यंत सराहनीय है.

मानवसेवा व पर्यावरण फाउंडेशन, भुसावल की तरफ से 'परिपूर्ण रेलवे समाचार' के संपादक सुरेश त्रिपाठी को स्मृतिचिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से, विधायक हरिभाऊ जावले, विधायक संजय सावकारे.

इस अवसर पर श्री त्रिपाठी के साथ ही प्रा. सुनील नेवे, डॉ. के. एम. शास्त्री, डॉ. गिरीश शास्त्री, प्रा. राहुल बारजीभे, डॉ. रिजवान खान, डॉ. अजहर शेख, पत्रकार नरेंद्र कदम, पत्रकार उज्वला बागुल, सुकन्या पवार, हाजी शफी पहलवान, रोमीसेठ आनंद, वी. के. लांजीवार, अरविंद वारके, पुलिस निरीक्षक प्रभाकर रायते, राजेंद्र सिंह राजपूत, एस. एस. सांगावार, श्रीकांत सराफ, संजय सिंह चव्हाण, गिरीश महाजन, बूटासिंह चितौड़िया, हाजी मुन्ना तेली, आसिक तेली और जी. आर. ठाकुर आदि को विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. यह सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह मानवसेवा व पर्यावरण फाउंडेशन की तरफ से शेख सत्तार, कैलाश शेलके, कलीम पायलट, अनिल सोनावने, जाकिर खान, नौशाद पहलवान और पवन बोरसे आदि पदाधिकारियों के अथक परिश्रम से संपन्न हुआ. कार्यक्रम का संचालन प्रा. उत्तम सुरवाड़े ने किया और उदय जोशी ने सभी उपस्थितों के प्रति आभार व्यक्त किया.

ट्रैकमैन भी हुए संगठित

सौंपा रेलवे बोर्ड को ज्ञापन

दिल्ली : हाल ही में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हजारों ट्रैकमैन (ट्रैक मेंटेनर) ने संगठित होकर 'रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन' (पंजीकृत) के महामंत्री जी. गणेश्वर राव के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया और रेलवे बोर्ड को विस्तृत ज्ञापन सौंपा. उल्लेखनीय है कि रेलवे में ट्रैकमैन की यही कैटेगरी सबसे ज्यादा दलित और दबी-कुचली हुई है. इस कैटेगरी का ही सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है. मगर अब हाल के वर्षों में इस कैटेगरी में हुई भर्ती से इसमें काफी पढ़े-लिखे लोग आए हैं, जो अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति न सिर्फ काफी जागरूक हैं, बल्कि उन्हें कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी भी पर्याप्त जानकारी उन्हें है. अब ट्रैक मेंटेनर की यह नई जमात शोषण सहने को तैयार नहीं है. इनकी मांगों पर रेलवे बोर्ड और सातवें वेतन आयोग को भी निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिए.

वर्ष 2014-15 के दौरान सबसे ज्यादा रक्तदान शिविरों का आयोजन करने के लिए वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ (डब्ल्यूआरएमएस) बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा सम्मानित किया गया. इस संबंध में 28 अगस्त को मुंबई के नायर अस्पताल में आयोजित एक समारोह में डब्ल्यूआरएमएस मुंबई मंडल के मंडल सचिव अजय सिंह को प्रशस्ति पत्र (मेरिट सर्टिफिकेट) प्रदान करती मुंबई की महापौर श्रीमती स्नेहल अम्बेकर. इस अवसर पर डब्ल्यूआरएमएस के जसवीर सिंह नोत्रा सहित अन्य सभी पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

वाईटीएसके के नाम पर यात्रियों को लूटने की साजिश –डॉ. भटनागर

वाईटीएसके के विरोध में सीआरएमएस की एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल

मुंबई : 'यात्री टिकट सेवा केंद्र' (वाईटीएसके) के रूप में रेल टिकट आरक्षण के निजीकरण के विरोध में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमएस) ने 25 अगस्त को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) सबर्बन लॉबी के सामने एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल कर रेल प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि वाईटीएसके को समाप्त नहीं किया गया, तो इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस संबंध में सीआरएमएस के मुख्यालय सचिव सफ़दर सिद्धीकी द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा देश के कांट्रेक्ट एक्ट 1970 का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है और रेल टिकट आरक्षण का नियमित कार्य वाईटीएसके के नाम पर ठेकेदारों एवं दलालों को दिया गया है, जो कि यात्रियों से अतिरिक्त चार्ज वसूल कर उनकी जेबें भरने में मदद कर रहा है. इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए सीआरएम एस के अध्यक्ष और एनएफआईआर के कार्याध्यक्ष डॉ. आर. पी. भटनागर ने कहा कि यात्री टिकट सेवा केंद्र के नाम पर रेलवे एक सोची-समझी साजिश के तहत आरक्षण काउंटर एजेंटों को दे रही है और सर्विस चार्ज के नाम पर रेल यात्रियों को लूट रही है. डॉ. भटनागर ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में रेलवे बोर्ड के मेंबर ट्रैफिक ने रेल संगठनों के साथ हुई एक बैठक में यह सुनिश्चित किया था कि आरक्षण काउंटर ठेकेदारों/एजेंटों को नहीं दिए जाएंगे.

सीआरएमएस के अध्यक्ष डॉ. भटनागर ने कहा कि इसके बावजूद रेल प्रशासन द्वारा वाईटीएसके के नाम पर रेल यात्रियों की जेबें काटने की साजिश को अंजाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धीरे-धीरे रेलवे को ठेके पर देने और इसकी तमाम सेवाओं का निजीकरण किए जाने की साजिश की जा रही है. डॉ. भटनागर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रेल मंत्रालय ने वाईटीएसके को बंद नहीं किया और यात्रियों के साथ की जा रही इस धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया गया, तो सीआरएमएस द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा. इस मौके पर सीआरएमएस के महामंत्री और एनएफआईआर के सहायक महामंत्री प्रवीण बाजपेई ने कहा कि रेल मंत्रालय ने जो वाईटीएसके एजेंटों को दिए हैं, वह यात्रियों को खुल्लमखुल्ला लूट रहे हैं. उन्होंने कहा कि वाईटीएसके एजेंटों द्वारा एसी के 40 रु. और स्लीपर के 30 रु. प्रति यात्री, यानि एक फॉर्म पर छह यात्रियों के लिए क्रमशः 240 रु. और 180 रु. वसूल किए जा रहे हैं. जबकि रेल आरक्षण केंद्र में यही आरक्षण शुल्क प्रति यात्री 15 रु. के हिसाब से छह यात्रियों के लिए मात्र 90 रु. ही दोनों श्रेणियों में लिया जाता है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेल दुनिया की सबसे सस्ती रेल सेवा है. श्री बाजपेई ने कहा कि भारतीय रेल द्वारा यात्रियों से फर्स्ट एसी के लिए प्रति किलोमीटर 1.50 रु., श्री एसी के लिए 1.00 रु. और स्लीपर क्लास के लिए मात्र 50 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया चार्ज किया जा रहा है. यदि इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए, तो यही किराया 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि सर्वसामान्य यात्रियों की खुलेआम लूट होगी. उन्होंने समान्य यात्रियों और नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे भी सरकार की इस मजदूर एवं आम जनता विरोधी नीति का खुलकर विरोध करें. श्री बाजपेई ने रेल प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि वाईटीएसके को अविलंब बंद नहीं किया गया, तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. इस एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल में सीआरएमएस के मुंबई मंडल अध्यक्ष वी. एस. सोलंकी, मंडल सचिव एस. के. दुबे, मुख्यालय सचिव सफ़दर सिद्धीकी, सहायक महामंत्री सुनील बेंडाले, अनिल राउत, विवेक शिशौदिया, डी. वी. रमण आदि सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भी भाग लिया.

'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चलीं भुनाने'

सुरेश त्रिपाठी

भारतीय रेल में पिछले करीब दो सालों से आंतरिक सुधार के बजाय वह सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी जरूरत सेकेंडरी है. जब भी कोई नया रेलमंत्री बनता है, वह अपनी तरह से भारतीय रेल को हांकना चाहता है. रेलमंत्रियों को उनकी इस हांक में उलझाकर भारतीय रेल की बेहद चापलूस नौकरशाही अपनी तिकड़मबाजियों को भरपूर अंजाम देने में लगी रहती है. जहां सबसे पहले देरी से चल रही भारतीय रेल की लगभग सभी यात्री गाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने को प्राथमिकता देने की सर्वाधिक जरूरत है, जहां मालगाड़ियों के समय निर्धारण और उनका गंतव्य पर सही समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, जहां भारतीय रेल में प्रतिदिन यात्रा करने वाले लगभग तीन करोड़ यात्रियों को बर्थ/सीट मुहैया कराए जाने की पहली चिंता की जानी चाहिए, जहां कम और लंबी दूरी की तेज गति गाड़ियां चलाकर करोड़ों यात्रियों के यात्रा समय को कम से कम किए जाने की फिक्र की जानी चाहिए, जहां रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) सहित तमाम जोनल मुख्यालयों और बड़े शहरों में 15-20 साल से लगातार बैठे हजारों रेल अधिकारियों को तुरंत दर-बदर करके भ्रष्टाचार की जड़ें काटे जाने की जरूरत है, जहां स्थानीय स्तर पर गहरे राजनीतिक संपर्क बनाकर भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत कर लेने वाले लंबे समय से एक ही जगह, एक ही शहर में जमे तमाम रेल अधिकारियों को हटाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है, जहां राजस्व की लीकेज रोकने के नाम पर खुद भ्रष्टाचार और पक्षपात में गहरे तक डूब चुके विभागीय सतर्कता संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाए जाने की जरूरत है, जहां अधिकारियों की मनमानी, लापरवाही पर कड़ी लगाम लगाए जाने की जरूरत है, सात नई जोनल रेलें बनने के बाद जहां बेलगाम बढ़ी अधिकारियों की संख्या को अविलंब कम किए जाने की अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी है, जहां अधिकारियों के घरों पर काम कर रहे लाखों रेलकर्मियों को बंधुआ मजदूरी से निकालकर उनके निर्धारित काम पर लगाए जाने की जरूरत है, जहां समय पर महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों की नियुक्तियां और उनकी एडवांस प्लानिंग किए जाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जहां एचओडी/पीएचओडी की नियुक्तियों में हो रहे पक्षपात और उनके प्रमोशन में हो रही अक्षम्य देरी को रोका जाना आवश्यक है, जहां सुरक्षा और संरक्षा कैटेगरी के लाखों पदों को भरे जाने को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जहां रेलकर्मियों में वेतन-भत्तों और कैरियर निर्धारण को लेकर फैले भीषण असंतोष को दूर किए जाने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जहां प्रमोशन में रिजर्वेशन को अविलंब खत्म किए जाने की जरूरत है, वहां सिर्फ दिवास्वप्न दिखाए जा रहे हैं और हवाई किले बनाए जा रहे हैं. रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करके करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं. साफ-सफाई के नाम पर सिर्फ ऊपरी कर्म-कांड करके रेल राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है. पैसेंजर एमिनिटी के नाम पर अनावश्यक कार्य करके करोड़ों का सार्वजनिक राजस्व स्वाहा किया जा रहा है. भारतीय रेल की ब्रांडिंग करने की भी तैयारी की जा रही है. इसी को कहते हैं 'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चलीं भुनाने'. जहां पहले रेलवे की आर्थिक स्थिति मजबूत किए जाने की जरूरत है, वहां ब्रांडिंग का तरीका एकदम भिन्न और आधुनिक बताया जा रहा है. अब रेलवे के नए शुभंकर और प्रतीक चिन्ह भी सामने आएंगे. इस ब्रांडिंग के जरिए रेलवे का पूरा हुलिया बदलने की तैयारी की जा रही है. इसमें स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों से लेकर ट्रेनों और डिस्प्ले बोर्डों के डिजाइन एवं रंग-रूप के मानक तय किए जाएंगे. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के साथ रेलवे ने समझौते किए हैं. ऐसा लगता है कि रेलवे में आजकल नए-नए आइडियाज की मानो बाढ़ आ गई है. कभी कोचों की आतंरिक साज-सज्जा (इंटीरियर्स) बदलने की बात हो रही है, तो कभी पूरी ट्रेन के बाहरी स्वरूप (एक्सटीरियर्स) और रंग पर प्रयोग किए जा रहे हैं. बिस्तर और तकिया पर सर्वे के परिणाम पहले ही सार्वजनिक हो चुके हैं. पर अभी तक इसका कोई माकूल परिणाम यात्रियों के सामने नहीं आ पाया है. कहा यह भी जा रहा है कि इन सबमें जल्दी ही कुछ और बेहतर रद्दोबदल किए जाने हैं. लेकिन रेलवे में इन तमाम कथित बदलावों का कोई मास्टर स्ट्रोक अभी तक सामने नहीं आया है. रेलवे की ब्रांडिंग के लिए एनआईडी के अलावा अन्य एजेंसियों की सेवाएं भी ली जा रही हैं. इसके तहत रेलवे में एकरूपता लाए जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है. इसमें रेलवे स्टेशनों, इमारतों और ट्रेनों, संकेतकों और सूचनापटों को एक खास रंग और डिजाइन में रंगना भी शामिल है. इसकी सफाई में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अभी रेलवे कई खेमों में बंटी दिखाई देती है, जिसमें हर जोन का अपना अलग हिसाब-किताब है. इनके चेहरों में भिन्नता नजर आती है. जैसे स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों, ट्रेनों और बोगियों में लगने वाले साइनेज अलग रंग-रूप और आकार-प्रकार के हैं. कहीं इनका रंग नीला है, तो कहीं पीला. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी अलग-अलग साइज के हैं. ट्रेनों का रंग भी अलग-अलग है. कुछ ट्रेनें नीली, तो कुछ मैरून कलर की हैं. जबकि कुछ को छींटदार हरे रंग में रंग दिया गया है. ब्रांडिंग के तहत इन्हें एक समान पैटर्न देने की कोशिश की जाएगी, ताकि मेट्रो की तरह भारतीय रेल की छवि भी आधुनिक हो सके और इसकी भी जोरदार मार्केटिंग की जा सके. फिलहाल यह जिम्मेदारी एनआईडी को दी गई है. हालांकि एनआईडी ने इसके लिए अतिरिक्त फंड की मांग की है. जबकि रेलवे ने पहले ही एनआईडी को दस करोड़ रुपए एडवांस में सौंप दिया है. लेकिन एनआईडी का कहना है कि इस राशि से ट्रेनों का डिजाइन तो सुधर सकता है, पूरी रेलवे का नहीं. इसलिए पहले एनआईडी को मनाने का प्रयास किया जा रहा हैं. यदि बात नहीं बनी, तो फिर ब्रांडिंग का जिम्मा किसी अन्य एजेंसी को सौंप दिया जाएगा. एनआईडी ने ट्रेन के बाहरी रंग-रूप के पांच नए प्रारूप उपलब्ध कराए हैं, जिन पर रेलवे बोर्ड में विचार चल रहा है. निफ्ड के सुझाए बेड रोल के शुरुआती डिजाइन रेलवे बोर्ड को पसंद नहीं आए थे, इसलिए उसे नए डिजाइन तैयार करने को कहा गया है. हालांकि ये सब काम भी किए जाने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु इस सारी कवायद में पूरा जोर बाहरी दिखावे पर ही दिया जा रहा है, जिसके बिना भी फिलहाल काम चल सकता है. मगर जिस आतंरिक सुधार की जरूरत है, और जो जरूरतें एवं आवश्यकाएं ऊपर बताई गई हैं, जिनके बिना किसी भी संस्था की आर्थिक नींव मजबूत नहीं हो सकती है, उन पर कतई कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. जबकि फंड की कमी और रेलवे की आर्थिक स्थिति ख़राब होने का रोना हर मंच पर रोया जा रहा है. ध्यान रहे कि जो लोग भूखे होते हैं, उन्हें फैशन की नहीं, पेट भरने के लिए पहले रोटी की जरूरत होती है. मगर आतंरिक तौर पर जर्जर होकर लगभग आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंच चुकी भारतीय रेल को मानो किसी फैशन परेड में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है. यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उपरोक्त तमाम बाहरी दिखावे वाली इन योजनाओं पर रेलवे बोर्ड के कुछ नौकरशाहों द्वारा ही खास रुचि ली जा रही है, क्योंकि ऐसी फालतू और दिखाऊ योजनाओं का सबसे पहला लाभ उन्हें ही मिलता है तथा इसी माध्यम से उनकी ऊपरी कमाई के अवैध रास्ते खुलते हैं. दूरंतो, राजधानी और शताब्दी गाड़ियों के बाहरी और भीतरी डिजाइन जैसे बाहरी दिखावे के कई काम पूर्व रेलमंत्रियों के कार्यकाल में किए गए. दूरंतो जैसी घटिया और फालतू डिजाइन की खरीद के लिए प्राथमिक तौर पर पचास लाख रुपए का भुगतान किया गया और अब तक करोड़ों रुपए की रायल्टी कोलकाता के अब तक सर्वथा अपरिचित चित्रकार को दे दी गई है. सवाल यह भी उठता है कि रेलवे से लाखों रुपए का वेतन प्रतिमाह ले रहे रेलवे के जो हजारों इंजीनियरिंग/मैकेनिकल अधिकारी और प्रशिक्षित डिजाइनर एवं ड्राफ्ट्समेन रेलकर्मी हैं, वह किस काम के लिए हैं?

कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर अकस्मात नहीं ढह जाता

- सभी रेल दुर्घटनाओं की जांच सीआरएस के बजाय किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जानी चाहिए
- हरदा रेल हादसे में खुद रेलवे की लापरवाही से गईं थीं 33 निर्दोष यात्रियों की जानें!

मध्य प्रदेश के खिरकिया-हरदा सेक्शन में 4 अगस्त को हुए भीषण रेल हादसे की प्रारंभिक जांच के बाद रेलवे विभाग खुद कटघरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है. हादसे की जांच कर रहे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) ने प्रथम दृष्टया रेलवे की लापरवाही को हादसे की वजह बताया है. सीआरएस के मुताबिक भारी बारिश की चेतावनी को अनदेखा किया गया. सीआरएस डी. के. सिंह जांच के लिए पिछले दिनों हरदा में थे. तीन दिनों तक हरदा और एक दिन भोपाल में डीआरएम कार्यालय में उन्होंने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की. इस दौरान घटना से जुड़े तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच में पता चला है कि मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया. रेलवे की तरफ से पहले यह कहा गया था कि बांध से अचानक पानी छोड़ने की वजह से हादसा हुआ. हालांकि, राज्य सरकार ने एक दिन बाद ही इन आरोपों को खारिज कर दिया था. अब रेलवे की अपनी जांच में भी इस बात पर मुहर लग गई है कि बांध से पानी छोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है.

सुरेश त्रिपाठी

बताया जा रहा है कि सीआरएस ने अपनी जांच में दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों को क्लीन चिट दे दी है. जांच में ये तथ्य सामने आया है कि कॉशन ऑर्डर नहीं होने की वजह से ड्राइवरों का तेज गति से ट्रेन चलाना गलत नहीं था. सीआरएस ने पेट्रोलिंग पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारी बारिश की वजह से लगातार पेट्रोलिंग की जाना थी, जो कि नहीं की गई. ट्रैक के आसपास पानी जमा होने की सूचना मिलने के बावजूद ऐहतियात नहीं बरती गई.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया रेलवे को नोटिस

मध्य प्रदेश के हरदा में 4 अगस्त की रात हुए ट्रेन हादसे का लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे को नोटिस दिया है. इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मामले का गंभीर मानते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को घटना की पूरी रिपोर्ट के साथ तलब किया है. आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को जबाव देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि रेलवे में हादसे का इस तरह का यह पहला मामला है, जिसमें दो ट्रेनें एक ही स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हुईं, जिसमें लाखों के जान-माल का नुकसान हुआ है. आयोग ने इसे रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही बताया है.

कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर अकस्मात नहीं ढ़ह जाता

इंजीनियरिंग विशेषज्ञों सहित रेलवे बोर्ड के कई सेवानिवृत्त मेंबर्स का कहना है कि यह दुर्घटना अत्यंत लापरवाही का परिणाम है. उनका कहना है कि कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर अकस्मात कभी नहीं ढ़हता. इसमें भारी लापरवाही बरती गई है. उनका यह भी कहना है कि दुर्घटना स्थल की स्थिति को देखने से कतई ऐसा नहीं लगता कि वहां अचानक 36 फुट ऊंचा पानी आ गया था. दुर्घटना के तुरंत बाद की तस्वीरों में वहां कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है. जबकि जो पानी वहां पुलिया के नीचे दिखाई दे रहा है, वह जमा हुआ दिख रहा है, उसमें कहीं भी बहाव के लक्षण नहीं दिख रहे हैं. इसके अलावा पुलिया का स्ट्रक्चर भी सही-सलामत दिखाई दे रहा है, जबकि दुर्घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर बरसाती नदी में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं है. ऐसे में यही लगता है कि दुर्घटना स्थल की पुलिया के दोनों ओर की अप्रोच मजबूत नहीं थी. यह अप्रोच धीरे-धीरे धंसक रही थी, मगर पेट्रोलिंग की कमी के कारण मंडल के इंजीनियरिंग अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया. इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का कहना है कि इंजीनियरिंग का यह पहला नियम है कि नियम पूर्वक निर्मित कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर (ढ़ांचा) अकस्मात नहीं ढह सकता, जब तक कि वह लम्बे समय तक अनदेखा नहीं किया गया हो. उल्लेखनीय है कि यह तलवड़िया से हरदा तक का वही पूरा रेल खंड है जिसका निर्माण सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में आने के कारण सरदार सरोवर प्राधिकरण द्वारा दी गई भारी राशि से पुरानी रेल लाइन को डूब क्षेत्र से हटाकर वर्ष 2002-03 में यह नई रेल लाइन बनाई गई थी. इसका निर्माण तब अविभाजित मध्य रेलवे के समय शुरू हुआ था, मगर इसका भुगतान अंततः विभाजित पश्चिम मध्य रेलवे के निर्माण संगठन द्वारा किया गया था. इस खंड के निर्माण में तब बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था. इस भ्रष्टाचार की कई खबरें तब 'रेलवे समाचार' ने प्रकाशित की थीं. इस भ्रष्टाचार के कारण ही यह भीषण रेल दुर्घटना हुई है, जिसमें 33 निर्दोष और निरीह रेलयात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. जबकि आश्चर्य इस बात का है कि इसके लिए अब तक किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अब ऐसी सभी रेल दुर्घटनाओं की जांच सीआरएस के बजाय किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि सीआरएस

रेलवे में 'शून्य दुर्घटना मिशन' शुरू किया जाए-रेलमंत्री

दिल्ली : रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारतीय रेल में जल्दी ही एक निश्चित समयावधि के साथ 'शून्य दुर्घटना मिशन' शुरू किया जाएगा. रेलमंत्री श्री प्रभु यहां 28-29 अगस्त को आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे. सम्मलेन का आयोजन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (आईआरएसटीई) (इंडिया) एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स (आईआरएसई) (इंडियन सेक्शन) द्वारा किया गया था. इस अवसर पर मुख्य लाइन, मेट्रो और उच्चगति वाली पारगमन प्रणाली के लिए कमान, नियंत्रण एवं संचार प्रणालियों की उन्नति पर भी अपने विचार रखते हुए रेलमंत्री ने कहा कि इसके लिए एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें कम लागत वाली उन्नत प्रौद्योगिकी और सही तरीके से प्रशिक्षित श्रमशक्ति का उपयोग शामिल होगा.

रेलमंत्री श्री प्रभु ने कहा कि कमान, नियंत्रण और संचार प्रणाली में नई प्रगति भारतीय रेल पर सुरक्षित और सुनिश्चित संचालन वातावरण विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है. ऐसे में मानवीय भूल की स्थिति में भी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं रहेगी. श्री प्रभु ने कहा कि रेलवे को अपने मानकों को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय रेलवे संकल्प जैसे एक अंतरराष्ट्रीय मंच का उपयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक बेंचमार्क पर ध्यान देना चाहिए और वैश्विक मानकों से अपनी स्थिति की तुलना करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हमें भारतीय रेलवे के अनुकूल वैश्विक मानकों वाली सस्ती प्रणालियां घरेलू स्तर पर विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए. रेलमंत्री ने रेलवे के सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर्स का आह्वान करते हुए कहा कि वे पूर्ण रूप से सुरक्षित रेलयात्रा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय कायम करके शून्य दुर्घटना मिशन (जीरो एक्सीडेंट मिशन) शुरू करें.

आईआरएसटीई (इंडिया) एवं आईआरएसई (इंडियन सेक्शन) द्वारा 'मुख्य लाइन, मेट्रो और उच्चगति वाली पारगमन प्रणाली के लिए कमान, नियंत्रण एवं संचार प्रणालियों की उन्नति' विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मलेन के समापन अवसर पर उपस्थित प्रबुद्ध रेलवे सिग्नल एवं टेलीकम्यूनिकेशन क्षेत्र के गणमान्य इंजीनियर्स को संबोधित करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु.

उन्होंने कहा कि रेलवे के समक्ष सुरक्षित परिवहन की एक बड़ी चुनौती है. रेलमंत्री ने कहा कि लोग हादसे के बिना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, इसके लिए हमें रेलवे एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग करके रेलवे में जीरो एक्सीडेंट मिशन शुरू करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमें ऐसी तकनीक की जरूरत है, जो मानवीय भूलों को भी नियंत्रित कर सके. श्री प्रभु ने रेलवे में जियो पोजिशनिंग और रिमोट तकनीक के भरपूर उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि हमें रेलवे से इतर विभिन्न क्षेत्रों में काम आने वाली तकनीक के भी रेलवे में इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि चौकीदार रहित रेलवे क्रासिंग की समस्या के समाधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की मदद से प्रयास किए जा रहे हैं. रेलमंत्री ने रेलवे में संसाधनों एवं क्षमता के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर इसमें काफी योगदान दे सकते हैं. विदेशों में उपलब्ध उन्नत तकनीक का आयात करने के बजाय उसे देखकर देश की जरूरतों के अनुसार विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि हम उस मामले में आत्मनिर्भर हो सकें. उन्होंने विभिन्न देशों के साथ तकनीकी सहयोग का उल्लेख करते हुए उन देशों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे भारत को अपना सामान एवं तकनीक मुहैया कराने के साथ साथ 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में भागीदार भी बनें.

पहले दिन सम्मलेन का उदघाटन करने के बाद चेयरमैन, रेलवे बोर्ड ए. के. मितल ने भी सम्मलेन को संबोधित किया. इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के मेंबर इलेक्ट्रिकल नवीन टंडन, एडिशनल मेंबर (सिग्नल) एस. मनोहर, एडिशनल मेंबर (टेलिकॉम) के. एस. कृष्णा कुमार और सेक्रेटरी/आईआरएसटीई एवं सीएसो/आईआरपीएमयू कुंदन चौधरी सहित बड़ी संख्या में रेलवे सिग्नल एवं टेलीकम्यूनिकेशन क्षेत्र के गणमान्य इंजीनियर उपस्थित थे.

महाप्रबंधक/उ.रे. द्वारा उ.रे. के विभिन्न ढाँचागत कार्यों की समीक्षा

महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ए. के. पुठिया द्वारा अपने सभी विभाग प्रमुखों के साथ उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, कश्मीरी गेट के कार्यालय में 28 अगस्त को उत्तर रेलवे पर चल रही विभिन्न ढाँचागत रेल परियोजनाओ की प्रगति की समीक्षा की गई. इस अवसर पर उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण बी. डी. गर्ग द्वारा महाप्रबंधक सहित सभी उपस्थित विभाग प्रमुखों को विभिन्न निर्माणाधीन रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण, आरओबी, आरयूबी, सीमित ऊँचाई वाले सब-वे, यातायात सुविधाओं, यांत्रिकी कारखाना, यात्री सुविधाओं की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी.

इस मौके पर महाप्रबंधक ए. के. पुठिया द्वारा सभी कार्यों की प्रगति को अन्य सम्बन्धित विभागों के तालमेल के साथ तेज करने के निर्देश दिए. गए. यह मीटिंग बहुत सफल रही तथा महाप्रबंधक द्वारा इस तरह के पुनर्वलोकन को प्रत्येक तीन महीनों के अंतराल पर करने के निर्देश दिए गए, जिससे सभी विभिन्न ढाँचागत परियोजनाओं के लक्ष्यों को निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके.

स्थापना दिवस पर उ.म.रे. आरपीएफ अधिकारियों एवं जवानों द्वारा रक्तदान

इलाहाबाद : 29 अगस्त से 4 सितंबर तक चल रहे आरपीएफ स्थापना दिवस समारोहों में विभन्न जानल रेलों के बल सदस्यों द्वारा भिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी परिप्रेक्ष्य में उ.म.रे. इलाहाबाद के रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों द्वारा आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, सूबेदार गंज में रविवार, 30 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर उपस्थित आईजी/सीएससी/आरपीएफ/ उ.म.रे. एन. के. सक्सेना, अपर आईजी/सीएससी/आरपीएफ/उ.म.रे. अजय सदानी एवं सीएमएस डॉ. आशीष अग्रवाल ने आरपीएफ जवानों को रक्तदान के महत्व और चिकित्सीय लाभ के बारे में बताया. इस रक्तदान शिविर में अजय सदानी, डॉ. आशीष अग्रवाल सहित कुल 55 आरपीएफ अधिकारियों एवं जवानों ने रक्तदान किया.

हमारी दक्षता रेलयात्री को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की होनी चाहिए –डीजी/आरपीएफ

- बल सदस्यों को महिलाओं एवं बच्चों के प्रति सम्वेदनशील रहते हुए समर्पित भाव से सेवारत रहना चाहिए
- आरपीएफ/आरपीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया

आरपीएफ/आरपीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बाएं से आईजी/आरपीएसएफ श्रीमती जया सिंह चौहान, डीजी/आरपीएफ राजीव रंजन वर्मा और डीआईजी/आरपीएसएफ.

दिल्ली : रेलवे सुरक्षा विशेष बल, छठी वाहिनी, दयाबस्ती के प्रांगण में 29 अगस्त को रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएफ/आरपीएसएफ) का 59वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक राजीव रंजन वर्मा तथा रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारियों द्वारा वाहिनी परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया. इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एंव जवानों को महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल राजीव रंजन वर्मा ने सभी बल सदस्यों को स्थापना दिवस की बधाई दी. महानिदेशक/आरपीएफ श्री वर्मा ने बल सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि रेलवे सुरक्षा बल कर्मी प्रतिदिन देश की आबादी के लगभग तीन करोड़ लोगों के संपर्क में आते हैं, जो देश की जीवन रेखा भारतीय रेल द्वारा देश के कोने-कोने में यात्रा करते हैं. हमें उनका अपेक्षित और वांछित सहयोग कर विश्वास अर्जित करके उनकी हरसंभव सहायता करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए. रेलवे सुरक्षा बल के समक्ष गरीब एवं अमीर व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने का महान अवसर उपलब्ध रहता है. उन्होंने कहा कि हमारी दक्षता न केवल उनको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के निमित्त होनी चाहिए, बल्कि वह जब भी हमारे सम्पर्क में आएं, उनके चेहरे पर मुस्कान परिलक्षित होनी चाहिए. हमें विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के प्रति सम्वेदनशील रहते हुए समर्पित भाव से सेवारत रहना चाहिए. श्री वर्मा ने सभी बल सदस्यों का आहवान करते हुए कहा कि हमें देश की प्रगति में योगदान करते हुए सुरक्षा बल को उन्नति के शिखर पर ले जाना है. इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा विशेष बल की महानिरीक्षक श्रीमती जया सिंह चौहान, रेलवे बोर्ड के महानिरीक्षक अपराध एवं आसूचना अनूप श्रीवास्तव तथा उत्तर रेलवे के महानिरीक्षक संजय किशोर भी उपस्थित थे.

आरपीएफ के स्थापना दिवस परेड की सलामी लेने के बाद आरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए (बाएं) दक्षिण पश्चिम रेलवे के आईजी/सीएससी/आरपीएफ डॉ. एस. सी. साहू और (दाएं) दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार सक्सेना. उनके साथ हैं आईजी/सीएससी/आरपीएफ डॉ. एस. सी. साहू. इस अवसर पर सीपीओ के. हरीकृष्णन एवं सभी विभाग प्रमुखों सहित डीआरएम/हुबली अरुण कुमार जैन भी उपस्थित थे. स्थापना दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हुए आईजी/सीएससी डॉ. साहू एवं अन्य आरपीएफ अधिकारी एवं जवान.

छपरा-बलिया-गाजीपुर-वाराणसी-इलाहाबाद रेल खंड के विद्युतीकरण का शिलान्यास

छपरा-बलिया-गाजीपुर-वाराणसी-इलाहाबाद रेल खंड के विद्युतीकरण कार्य का शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा. मंच पर विराजमान हैं महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, राजीव मिश्रा एवं अन्य गणमान्य.

वाराणसी : रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर 17 अगस्त को आयोजित एक समारोह में छपरा-बलिया-गाजीपुर-वाराणसी-इलाहाबाद रेल खंड के विद्युतीकरण का शिलान्यास एवं कार्य शुभारम्भ फलक का अनावरण किया. इस अवसर पर समारोह को सम्बोधित करते हुये रेल राज्यमंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-बलिया-गाजीपुर-वाराणसी-इलाहाबाद रेल खंड को 415 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गयी है. इस विद्युतीकरण कार्य को 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. विद्युतीकरण का यह कार्य रेल मंत्रालय के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है. इस परियोजना के पूरा होने पर इस रेल खंड पर तीव्रगामी मेमू एवं लम्बी दूरी की विद्युत चालित गाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा. यह रेल खंड मुख्य रेल मार्ग से सुविधाजनक तरीके से जुड़ जाएगा तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्वि होगी.

रेल राज्यमंत्री ने कहा कि रेल विद्युतीकरण होने से गाड़ियों के संचालन में न्यूनतम ऊर्जा की खपत होती है. अधिक हार्स पावर के विद्युत इंजनों के उपयोग से अधिक कोच एवं वैगनों की ढुलाई

■ अगले 4 वर्षों में 10,000 किमी. रेल खंड के विद्युतीकरण का लक्ष्य

सुविधाजनक तरीके से होती है तथा विद्युत इंजनों के उपयोग से डीजल खपत में कमी होने के कारण विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा थ्रू-पुट बढ़ने से लाइन क्षमता में वृद्वि भी होगी. इससे पर्यावरण का भी बचाव होगा. श्री सिन्हा ने कहा कि भारतीय रेल पर 40 प्रतिशत रेल खंडों का विद्युतीकरण हो चुका है. इन विद्युतीकृत रेल खंडों से 66 प्रतिशत भालभाड़े की ढुलाई होती है एवं 51 प्रतिशत यात्री भी इन खंडों से यात्रा करते हैं. उन्होने कहा कि अभी तक भारतीय रेलों पर प्रतिवर्ष 1200 से 1300 किमी. रेल खण्ड का विद्युतीकरण होता रहा है, जबकि अब से अगले चार वर्षों में 10,000 किमी. रेल खंड के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है.

रेल राज्यमंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि 51 किमी. लम्बी मऊ-ताड़ीघाट नई रेल लाइन निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. गाजीपुर जनपद के वाराणसी मंडल के अन्तर्गत दोहरीकरण, सीमित ऊंचाई के भूमिगत मार्गों सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुख-सुविधाओं में विस्तार की परियोजनाएं चल रही हैं. इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने कहा कि 330 किमी. लम्बे छपरा-बलिया-गाजीपुर-वाराणसी-इलाहाबाद रेल खंड के विद्युतीकरण कार्य को रेल मंत्रालय द्वारा 415 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृति प्रदान कर जुलाई 2014 के पिंकबुक में शामिल किया गया था. श्री मिश्रा ने कहा कि इस विद्युतीकरण परियोजना के अन्तर्गत 220/132 केवी के पांच सब-स्टेशन एवं छह मेन्टीनेन्स डिपो बनाए जाएंगे तथा 12 स्टेशनों की सिग्नलिंग का अपग्रेडेशन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 36 महीनों में पांच चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी. महाप्रबन्धक श्री मिश्रा ने कहा कि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर उन्नत यात्री सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें वाई-फाई की सुविधा भी सम्मिलित है. इसके अतिरिक्त यहां एस्केलेटर, पैदल उपरिगामी पुल, प्लेटफार्म संख्या 1 एवं 2 के विस्तारीकरण एवं वीआईपी लाउन्ज के निर्माण का कार्य प्रगति पर है. रेल राज्यमंत्री एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सतीश अग्निहोत्री ने परियोजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में गाजीपुर-वाराणसी खंड पर दिसम्बर 2016 तक, बलिया-गाजीपुर एवं वाराणसी-माधोसिंह खंड पर मार्च 2017 तक, माधोसिंह-इलाहाबाद खंड पर दिसम्बर 2017 तक तथा छपरा-बलिया रेल खंड पर विद्युतीकरण का कार्य जून 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा. इस मौके पर मंडल रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी सतीश के. कश्यप ने रेल राज्यमंत्री सहित सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया. समारोह का संचालन पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री संजय यादव ने किया.

रेलकर्मियों के लिए भी 'वन रैंक वन पेंशन' की मांग

सैनिकों की तरह रेल कर्मचारी भी 24 घंटे काम करते हैं
-डॉ. एम. राघवैया

रक्षाकर्मियों की तरह रेलकर्मी भी देश के लिए ही अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं
-कॉम. शिवगोपाल मिश्रा

दिल्ली : एक तरफ पूर्व सेनानी वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर सालों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय रेल के करीब 13.36 लाख रेलकर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाली रेलवे की दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों ने रेल कर्मचारियों के लिए भी 'वन रैंक वन पेंशन' की मांग शुरू कर दी है. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआइआर) का कहना है कि रेल कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए. एनएफआइआर ने रेलवे में निजीकरण का भी पुरजोर विरोध किया है.

एनएफआइआर के महामंत्री डॉ. एम. राघवैया का कहना है कि सैनिकों की तरह रेल कर्मचारी भी 24 घंटे काम करते हैं. इसलिए उन्हें भी वन रैंक वन पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. यह देशहित और जनहित में नहीं है. उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों की संख्या बहुत भी घट गई है. जबकि एक समय था जब रेलवे में स्थायी कर्मचारियों की संख्या 17 लाख से भी ज्यादा थी, जो अब घटकर 13 लाख 36 हजार रह गई है. डॉ. राघवैया ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में और कमी करने की बात चल रही है, जबकि यात्री और मालगाड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

एनएफआइआर के महामंत्री ने कहा कि विवेक देबराय कमेटी की रिपोर्ट आते ही रेलकर्मियों को रेलवे के निजीकरण का डर सताने लगा है. रेल में 100% एफडीआई के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं. इसका सभी रेलवे के सभी कर्मचारी संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 84 एकड़ तथा मुंबई में लगभग 12 एकड़ रेलवे की जमीन लीज पर देने की तैयारी है. इन वेशकीमती जमीनों पर भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए आवास, अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान बनने चाहिए, लेकिन सरकार इसे बेच रही है. एनएफआईआर के मीडिया प्रभारी एस. एन. मलिक एवं यूआरएमयू के महामंत्री बी. सी. शर्मा ने कहा रेलवे में निजीकरण का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं. इस संबंध में प्रधानमंत्री और रेलमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है.

रेलवे कर्मचारियों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) की मांग को सर्वप्रथम उठाने वाले ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलकर्मियों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रक्षाकर्मियों की तरह रेलकर्मी भी रात-दिन देश के लिए ही अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं. कॉम. मिश्रा ने बताया कि सातवें वेतन आयोग में रेल कर्मचारियों के लिए ओआरओपी के मुद्दे पर चर्चा हुई है और फिर से यह मामला उठाया जाएगा.

कॉम. मिश्रा ने कहा कि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और रेल कर्मचारी चौबीसों घंटे देश के लिए समर्पित सेवा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रक्षा बलों में सैन्यकर्मियों को ओआरओपी मिलना चाहिए, लेकिन यही सिद्धांत रेलवे पर भी लागू किया किया जाना चाहिए. सर्वाधिक रेलकर्मियों का नेतृत्व करने वाले एआईआरएफ के महामंत्री कॉम. मिश्रा ने कहा कि सेना में हमारे भाईयों को जितनी जल्दी मुमकिन हो यह समानता मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही रेलकर्मियों को भी नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

मेल/एक्स. से दैनिक यात्रा करने वाले कर्मचारियों पर लगाम

मुंबई : मध्य रेलवे प्रशासन ने एक फरमान जारी करते हुए रेल कर्मचारियों को हिदायत दी है कि बिना परमीशन अथवा प्रॉपर अथॉरिटी के ऑन ड्यूटी मेल/एक्स. ट्रेनों के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करना प्रतिबंधित है. रेल प्रशासन ने यात्रियों की शिकायत के बाद इस मामले में संज्ञान लेते हुए रेल कर्मचारियों को लिखित हिदायत दी है. सीनियर डीसीएम/मुंबई मंडल, मध्य रेलवे, सीएसटी डॉ. आलोक बड़कुल ने कहा है कि मेल/एक्स. के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते पकड़े जाने वाले रेलकर्मी बिना टिकट माने जाएंगे और उनसे नियमानुसार चार्ज वसूल किया जायेगा.

उ.रे. द्वारा माल ढुलाई में अपेक्षित वृद्धि पर संगोष्ठी

दिल्ली : उत्तर रेलवे ने थ्रुपुट (सीधा माल यातायात) में अपेक्षित वृद्धि और माल यातायात बढ़ाने के लिए मालभाड़ा व्यवसाय पर 25 अगस्त को उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया. संगोष्ठी की अध्यक्षता, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ए. के. पुठिया ने की. इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक एस. के. पाठक, मुख्य परिचालन प्रबंधक संजीव गर्ग एवं सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे. उत्तर रेलवे के भारतीय खाद्य निगम, उर्वरक कम्पनियां, टाटा कैमिकल लिमिटेड, ईफको जैसे बड़े-बड़े उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि एवं सम्बद्ध मल्टी मॉडल सहित कॉनकोर, अक्टो (कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों की एसोसिएशन) आदि उपस्थित थे. इसके अलावा मारूति सुजुकी, सोनालिका ट्रेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल ग्राहकों ने भी इस संगोष्ठी में भाग लिया.

महाप्रबंधक ने कहा कि उत्तर रेलवे खाद्यान्न, उर्वरक आदि सभी प्रमुख उद्योगों के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने सभी उद्योगों के साथ निरंतर सहयोग बनाए जाने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कहा कि इनमें रेलवे का हिस्सा और बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. संगोष्ठी में भाग लेने वाले सदस्यों ने उनके सामने आने वाली कठिनाईयों का उल्लेख किया और रेलवे उनको किस प्रकार बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध करा सकती है, इस बारे में भी बताया. जिन क्षेत्रों से वृद्धि कम हुई है, उन क्षेत्रों में रेल ट्रेफिक बढ़ाने के लिए अधिकरियों ने उपयुक्त रणनीति के बारे में बताया. खाद्यान्न एवं उर्वरक क्षेत्रों को सुझाव दिया गया कि कम वयस्त अवधि के ट्रेफिक डिस्काउंट एवं सरप्लस वैगन उपलब्धता के जरिए अपने परिवहन खर्चे

ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस की सुविधा

इलाहाबाद : रेल प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों को सुखद एवं साफ-सुथरी रेल यात्रा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में यात्रा के दौरान रेल गाड़ियों के अंदर साफ-सफाई को और बेहतर बनाने की दृष्टि से इलाहाबाद मंडल की ट्रेनों में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) की सुविधा प्रदान की गई है. यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की साफ-सफाई संबंधी शिकायतों को केंद्रीयकृत कंट्रोल में दर्ज कराया जा सकता है, जहां से इन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा. मोबाइल नंबर 9794837755 के माध्यम से रेलयात्री अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. यह मोबाइल नंबर रेलगाड़ियों के डिब्बों में भी अंकित किया गया है.

भा.रे. की स्थिति आईसीयू में भर्ती मरीज...

पेज 1 का शेष... से अक्तूबर में शुरू होता है, इस समय माल ढुलाई के लिए मांग बढ़ती है. उन्होंने कहा कि रेलवे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. रेलमंत्री ने कहा कि रेल बजट में घोषित योजनाओं में से 79 योजनाओं को क्रियान्वित किया जा चुका है. पिछले 15-20 साल के दौरान रेलवे में कोई उल्लेखनीय क्षमता नहीं जोड़ी गई, जबकि दिल्ली-हावड़ा जैसे रेल मार्ग का उसकी क्षमता से अधिक उपयोग हो रहा है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने रेलवे में पर्याप्त निवेश नहीं किया है. इसके आधुनिकीकरण से बचा गया, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि अगले पांच साल के दौरान रेलवे में 120 अरब डालर का निवेश किया जायेगा. महाराष्ट्र ने अगले चार साल में रेलवे में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने पर सहमति जताई है. इसके अलावा 16 अन्य राज्यों ने भी इस पर सहमति जताई है.

रेलमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) एवं कोल इंडिया ने रेलवे में निवेश करने की इच्छा जताई है. ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा.

बहरहाल, यह रोना पिछले डेढ़ साल से रेलमंत्रियों द्वारा लगभग अपनी सभी तकरीरों और सभी मंचों पर रोया जा रहा है, मगर इसे बाहरी चश्मे से देख रहे रेलमंत्री इसकी सड़ चुकी अंदरूनी स्थिति को ठीक करने के बजाय उसे लगातार नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं. इसके अलावा जिन रेल अधिकारियों की अकर्मण्यता की बदौलत क्षमता के अनुरूप माल ढुलाई न मिलने के कारण आज भारतीय रेल आईसीयू में भर्ती हुई पड़ी है, उन अकर्मण्य रेल अधिकारियों को चुस्त-दुरुस्त करने का कोई प्रयास रेलमंत्री ने अब तक नहीं किया है. रेलवे की खराब स्थिति को गंभीरतापूर्वक सुधारने के बजाय रेलमंत्री द्वारा लगभग हर मंच पर इसकी खराब स्थिति का लगातार रोना रोया जा रहा है. रेलवे में चौतरफा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रेलमंत्री ने संसद में खुद इस बात को स्वीकार किया है, इसके बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ अब तक कोई कदम नहीं उठाया है.

करीब चार साल बाद मिला मेट्रो रेलवे को...

पेज 1 का शेष... विद्युत अभियंता (सीईई) के पद पर कार्यरत थे. श्री अश्विनी कपूर को भारतीय रेल के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का गहन अनुभव प्राप्त है. वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत सक्षम अधिकारी माने जाते हैं. उल्लेक्नीय है कि पी. बी. मूर्ति के बाद लगभग चार साल के पश्चात मेट्रो रेलवे, कोलकाता को अपना नया महाप्रबंधक मिला है. उधर, रेलवे बोर्ड और सेक्रेटरी/डीओपीटी के बीच जीएम पैनल को लेकर खींचतान लगातार जारी है. इसी वजह से अब तक नया जीएम पैनल फाइनल नहीं हो पाया है. हालांकि रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2015-16 के जीएम पैनल में शामिल कुल 27 वरिष्ठ रेल अधिकारियों की डीपीसी पूरी कर ली गई है. अब जल्दी ही इन 27 अधिकारियों का यह नया पैनल डीओपीटी को भेज दिया जाएगा. जबकि डीओपीटी के हमारे सूत्रों का कहना है कि जब तक रेलवे बोर्ड द्वारा जीएम और डीआरएम बनाए जाने वाले नियमों को सही एवं स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं किया जाएगा, और इन्हें डीओपीटी के समक्ष प्रस्तुत करके उसकी पर्याप्त सहमति नहीं ले ली जाती है, तब तक डीओपीटी से रेलवे बोर्ड द्वारा भेजे जाने ऐसे किसी पैनल को अपनी मंजूरी नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, 'रेलवे समाचार' को इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य पता चला है. वह यह कि सेक्रेटरी/डीओपीटी द्वारा नियमों की स्पष्टता की आड़ में उतर रेलवे में कार्यरत वर्ष 1983 बैच के अपने एक सगे सम्बंधी रेल अधिकारी को भी जीएम पैनल में समाहित किए जाने के लिए ही रेलवे बोर्ड के साथ यह अड़ीबाजी की जा रही है. हालांकि, हमारे सूत्रों ने इस अटकलबाजी को रेलवे बोर्ड के कुटिल अधिकारियों द्वारा चली गई एक चाल बताया है, जिससे एक तरफ सेक्रेटरी/डीओपीटी द्वारा नियमों की स्पष्टता के लिए की जा रही वाजिब जिद से बचा जा सके, तो दूसरी तरफ इस तरह का तथ्यहीन विवाद खड़ा करके सेक्रेटरी/डीओपीटी को बदनाम भी किया जा सके. सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित जीएम पैनल में अभी सिर्फ वर्ष 1979 बैच तक के ही वरिष्ठतम रेल अधिकारियों का ही समावेश किया जा रहा है. अतः वर्ष 1983 बैच के अमूमन कनिष्ठ रेल अधिकारी का नाम शामिल किए जाने की बात हास्यास्पद ही कही जाएगी. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार और सम्बंधित मंत्रियों को गुमराह करने और दो मंत्रालयों के बीच अनावश्यक विवाद खड़ा करने के लिए अपने-अपने निहितस्वार्थ में कुछ नौकरशाहों द्वारा ऐसी कई कुटिल चालें अक्सर चली जाती हैं, जिससे अपना-अपना उद्देश्य हासिल किया जा सके. जबकि रेल मंत्रालय ने रेलवे में अभी तक हर साल या प्रत्येक रेल परियोजना में मनमानी और फालतू वर्कचार्ज पोस्टों को क्रिएट किए जाने सम्बंधी स्पष्टीकरण भी डीओपीटी को नहीं दिया है, जिससे यह मामला भी अब तक दोनों मंत्रालयों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है.

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 4 महीने आगे...

पेज 1 का शेष... अखिल भारतीय स्तर के बड़े श्रमिक संगठनों का मानना है कि 23 नवंबर की प्रस्तावित रेलवे सहित सार्वजनिक देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने की समय-सीमा आगे बढ़ा दी है. उनका कहना है कि 23 नवंबर की हड़ताल पर अड़े श्रमिक संगठनों पर सरकार की यह दबाव बनाए जाने की अप्रत्यक्ष रणनीति है, मगर इस परिप्रेक्ष्य में श्रमिक संगठन सरकार के किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं. श्रमिक संगठनों का कहना है कि श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण केंद्रीय कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी असंतोष उभर रहा है. वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने की तारीख आगे खिसकाकर और 2 सितंबर की हड़ताल में पलीता लगाने की कोशिश करके सरकार ने आग में घी डालने का काम किया है. अब यह आग 23 नवंबर की हड़ताल में अपना विकराल रूप दर्शाएगी.

अवैध रेलवे क्रासिंग बंद करने के प्रति कब सचेत होगा रेल प्रशासन?

पेज 1 का शेष... 'रेलवे समाचार' ने राजेंद्रनगर टर्मिनल के पास स्थित अवैध सब्जी मंडी और अवैध रेलवे क्रासिंग के यहां प्रस्तुत ये तीन फोटोग्राफ प्रकाशित करते हुए यहां फुट ओवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया था, तब पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के तौर पर मधुरेश कुमार ने अपनी अवैध कमाई की तिकड़मबाजियों में लिप्त होने के कारण इस महत्वपूर्ण सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया था.

इस संबंध में 'रेलवे समाचार' द्वारा पहले भी कई बार लिखा जा चुका है. इसके साथ ही सुझाव भी दिया गया था कि राजेंद्रनगर टर्मिनल के दिल्ली/पटना छोर पर प्लेटफ़ॉर्म 4, 3, 2 पर फुट ओवर ब्रिज बनाते हुए मात्र 40 मीटर दूर पर स्थित आरओबी से इसका मिलान कर दिया जाए. जैसे इलाहाबाद और कोलकाता में किया गया है. संरक्षा और सुरक्षा के लिए यह जरुरी है. साथ ही इससे आम जनता को भी बहरी सहूलियत हो जाएगी. प्लेटफार्म 1 को और आगे आरओबी तक बढ़ाकर अतिरिक्त प्लेटफार्म बना देना चाहिए, क्योंकि वहां इसके लिए अभी पर्याप्त जगह है. मगर रेल प्रशासन को इन सुझावों की सुधि आजतक नहीं आई है.

वर्तमान में भी इस छोर (एप्रोच) पर भाजी मंडी अनाधिकृत रूप से लग रही है, जिससे लोगों को आने-जाने के लिए काफी संकीर्ण जगह ही बचती है. इस जगह को प्रोटेक्ट करते हुए रिजर्वेशन काउंटर भी इस तरफ बनाया जाना चाहिए. इसके अलावा निकास द्वार भी बनाना चाहिए, जहां टिकट निरीक्षकों द्वारा जांच होने से रेल राजस्व का भी फायदा होगा. चूंकि 98% यात्री ट्रेन से उतरकर इसी छोर से राजेंद्रनगर या पटना शहर की ओर निकल जाते हैं. लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक रेल प्रशासन द्वारा इसी छोर को लावारिश छोड़ कर रखा गया है, जबकि यहां ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय और रेलवे की घोर लापरवाही का उदाहरण हैं. इस भीषण घटना के बाद यहां रेलकर्मियों के बीच इस बात की चर्चा थी कि राजेंद्रनगर टर्मिनल पर ऐसा हादसा कभी-भी हो सकता है, यह मुद्दा तो 'रेलवे समाचार' द्वारा बहुत पहले ही उठाया गया था, लेकिन रेल प्रशासन ने इसे हलके में लिया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है. राजेंद्रनगर टर्मिनल पर हुई उपरोक्त दुर्घटना के बाद पूरा रेल प्रशासन अब ऐसी अवैध रेलवे क्रासिंग को बंद करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करने में जुट गया है. दानापुर मंडल क्षेत्र में ऐसी 77 अवैध रेलवे क्रासिंग हैं. इनमें से एक दर्जन से अधिक ऐसी रेलवे क्रासिंग हैं, जहां आए दिन कोई न कोई व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठता है. पिछले करीब छह वर्षों के दौरान सिर्फ पटना जिले में 5500 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है.

राजधानी पटना में चितकोहरा, फुलवारी शरीफ, पटना जंक्शन के मीठापुर, चिरैयाटांड़ पुल के पास, लोहानीपुर, राजेंद्रनगर टर्मिनल, राजेंद्रनगर कोचिंग कांप्लेक्स, गुलजारबाग स्टेशन के दोनों तरफ, पटना-गया रेल खंड पर सिपारा, डूमरी हाल्ट के पास, तारेगना आदि जगहों पर स्थानीय जनता को जबरन या मजबूरन रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है. मीठापुर एवं राजेंद्रनगर टर्मिनल के पास बाकायदा अवैध सब्जी मंडी बना ली गई है. इन दोनों जगहों पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं. रेलवे पुलिस के एसपी प्रकाश नाथ मिश्रा के अनुसार ट्रेन से कटकर मरने वालों में महिलाओं की संख्या भी काफी है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में 907 लोगों के ट्रेन से कटने से मौत हो गई, जिसमें 161 महिलाएं थीं. जबकि वर्ष 2011 में हुई 989 मौतों में से 171, 2012 में 947 में से 191, 2013 में 967 में से 168, 2014 में 1015 में से 174 महिलाएं एवं जून 2015 तक 502 लोगों के ट्रेन से कटकर मरने वालों में से 85 महिलाएं हैं. यदि अब भी जिला एवं रेल प्रशासन ने इन अवैध रेलवे क्रासिंग को स्थाई रूप से बंद करने का गंभीर प्रयास नहीं किया, तो निकट भविष्य में पुनः उसे जनसामान्य के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है.

'रेलवे समाचार' ने करीब दो साल पहले मधुरेश कुमार के पूर्व मध्य रेलवे का महाप्रबंधक रहते प्रकाशित किए थे ये तीनों प्रस्तुत फोटोग्राफ

अपनी खाल बचाने हेतु रे.बो. ने उठाया श्रीधरन की क्षमता पर सवाल...

पेज 1 का शेष... पहले ही आठ साल की देरी हो चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 111 किमी. लंबी कटरा-बनिहाल लाइन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए श्री श्रीधरन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी. यह समिति इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान बनाई गई थी.

उल्लेखनीय है कि उक्त रेलवे लाइन सेक्शन के निर्माण में पिछले 13 वर्षों के दौरान भारतीय रेल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है. श्रीधरन समिति ने फरवरी में यह रिपोर्ट दी थी. उसमें कहा गया था कि मौजूदा अलाइनमेंट के साथ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भूस्खलन, भूकंप से पैदा होने वाले खतरों और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद होने के कारण सुरक्षा संबंधी जोखिम के सामने सुरंगों और पुलों की सुरक्षा का मामला बेहद कमजोर है. परंतु रेलवे बोर्ड ने श्रीधरन समिति की रिपोर्ट के नतीजों को खारिज कर दिया था. रेलवे बोर्ड का कहना था कि समिति का कोई भी मेंबर साइट पर गया ही नहीं और समिति ने प्रॉजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से बात नहीं की थी.

यही नहीं, इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के वर्तमान तथाकथित काबिल अधिकारियों ने कोंकण रेलवे के 'सेफ्टी रिकॉर्ड' पर भी सवाल उठाए और उस लाइन पर अब तक हुई दुर्घटनाओं की रिपोर्ट सामने रखी, जिनमें कुल 71 यात्रियों की मौत हुई है. रेलवे बोर्ड ने कहा कि विशेषज्ञ लोग भी गलतियां कर सकते हैं. रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा कि दूसरी ओर जम्मू-बारामुला लाइन पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है, जिसे कहीं ज्यादा मुश्किल भौगोलिक स्थितियों में बनाया गया है. श्रीधरन ने कहा कि रेलवे ने उनकी रिपोर्ट या कोंकण रेलवे के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसका जवाब वह कोर्ट में ही देंगे. कुछ अधिकारियों ने बताया कि कटरा-बनिहाल लाइन पर पीएमओ की नजर है और वह चाहता है कि इस मामले में रेलवे कड़ा रूख अपनाए.

बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाइन के बारे में रेल मंत्रालय से नियमित तौर पर रिपोर्ट देने को कहा है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार अपनी खाल बचाने के लिए अब पीएमओ का सहारा लिया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि पीएमओ को इस प्रॉजेक्ट की देरी की मुख्य वजह उक्त पीआईएल बताई गई है. दो दशक पहले श्रीधरन और उनकी टीम ने अत्यंत कथित परिस्थितियों में कोंकण रेलवे का निर्माण किया था. जबकि उससे पहले दूसरी टीमों के कई प्रयास विफल हो गए थे. समुद्र तट के पास होने से भारी मानसूनी बारिश से उस लाइन पर भूस्खलन का खतरा रहता है. श्रीधरन के नेतृत्व में बनी दिल्ली मेट्रो को भारत में सबसे ज्यादा सफल मासट्रांजिट सिस्टम माना जाता है. ऐसे में जिस व्यक्ति को 'भारत रत्न' दिया जाना चाहिए, उसकी क्षमता पर रेलवे की नई पीढ़ी की नामुराद औलादों ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया है.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सर्वोच्च प्राथमिकता है -अरुण सक्सेना

- राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं इसकी समृद्धि के लिए अपने आपको समर्पित करें रेलकर्मी
- यात्रियों की सुरक्षा हमारा सर्वोपरि दायित्व है
- यात्रियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करना ही हमारी प्रतिबद्धता है

इलाहाबाद : उत्तर मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय, इलाहाबाद में 15 अगस्त को राष्ट्र का 69 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. कार्यक्रम का शुभारम्भ महाप्रबंधक अरुण सक्सेना द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ. इस अवसर पर महाप्रबंधक ने उत्तर मध्य रेलवे के सभी कर्मचारियों, जवानों, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों एवं उनके परिजनों को गौरवशाली राष्ट्र के 69वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दिन. उन्होंने कहा कि इस गरिमापूर्ण अवसर पर हम देश की उन महान विभूतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. यह उन्हीं महापुरुषों की देन है कि आज हम स्वाधीनता के प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को गर्व के साथ फहरा रहे हैं. अतः इस पुनीत अवसर पर हम राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं उसकी समृद्धि के लिए अपने आपको समर्पित करें.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की जीवन रेखा भारतीय रेल के प्रमुख अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उ.म.रे., देश के उत्तरी भाग को दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी भागों से जोड़कर देश की एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष जून, 2015 तक हमारी कुल आनुपातिक आय में 18.91% की वृद्धि हुई है. इसी तरह मालभाड़ा आमदनी में भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20.57% की उत्साहजनक वृद्धि हुई है. वर्ष 2014-15 के दौरान उ.म.रे. को स्क्रैप की बिक्री से 248.70 करोड़ रुपए की रिकार्ड आमदनी हुई, जो रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित कठिन लक्ष्य से भी अधिक है. चालू वित्त वर्ष में भी उ.म.रे. प्रगति की ओर अग्रसर है और प्रथम तिमाही के दौरान ही स्क्रैप की बिक्री से 36.89 करोड़ रुपए का अर्जन हो चुका है. महाप्रबंधक ने कहा कि गाड़ियों का सुरक्षित एवं संरक्षित संचालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. गाड़ी परिचालन में संरक्षा और विश्वसनीयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के दौरान 9 स्टेशनों तथा वर्ष 2015-16 के दौरान इलाहाबाद मंडल के इटावा एवं नैनी स्टेशनों सहित 5 स्टेशनों पर इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग चालू की गई. इस प्रकार उ.म.रे. के 119 स्टेशनों पर इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग चालू की जा चुकी है. इस वित्त वर्ष के दौरान जून, 2015 तक विभिन्न समपार फाटकों के स्थान पर 19 ऊपरी सड़क पुलों, निचले सड़क पुलों तथा सीमित ऊँचाई के भूमिगत मार्गों का निर्माण कराया जा चुका है और 5 पुलों का नवीनीकरण भी किया गया है. वर्ष 2014-15 के दौरान 61 समपार फाटकों पर स्लाइडिंग बूम लगाए गए हैं. 7 समपार फाटकों पर विद्युत चालित लिफ्टिंग बैरियर लगाने के साथ ही 6 नए समपार फाटकों की इंटरलॉकिंग भी की गई है.

उन्होंने कहा कि हमारे लोको पायलट विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं. इन्होंने अपनी सतर्कता से पिछले एक वर्ष के दौरान न केवल 34 संभावित दुर्घटनाओं को बचाया, बल्कि तीन फेज विद्युत इंजनों में विद्युत ऊर्जा का पुनः उत्पादन कर 25 करोड़ रुपए की बचत भी की है. ग्राहकों की सुविधा के लिए इस वर्ष कानपुर से जम्मूतवी के लिए एक नई गाड़ी का संचालन प्रारंभ किया गया है. यात्रियों को आसानी से टिकट उपलब्ध कराने हेतु 30 नए जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों की नियुक्ति की गई है. आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु उ.म.रे. पर यात्री टिकट सुविधा केंद्र की एक नई योजना प्रारंभ की गई है. उ.म.रे. में पहली बार जून माह से क्रिस द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेब आधारित ऑनलाइन रिफंड प्रणाली की शुरुआत की गई है.

यात्रियों की सुरक्षा हमारा सर्वोपरि दायित्व है. रेलमंत्री द्वारा बजट भाषण में किए गए वादों के अनुपालन में उ.म.रे. में अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्प लाइन नंबर 182 तथा शिकायत नंबर 138 चालू कर दी गई है. रेलवे सुरक्षा बल के महिला दस्ते द्वारा महिला यात्रियों की सहायता में पूरी मुस्तैदी के साथ दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है. इनकी सक्रियता से उ.म.रे. में 7278 मामलों को संज्ञान में लिया गया है. हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपने परिवार से बिछुड़े 35 बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है. सतर्कता विभाग द्वारा रेलवे की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 10 नए प्रणालीगत सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं. अपने समर्पित कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से योग शिविरों का आयोजन किया गया. कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय अस्पताल, इलाहाबाद में घुटने को पूरी तरह से बदलने की सर्जरी प्रारंभ की गई है. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पांच और निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध भी किया गया है. प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया प्रोग्राम में सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से झांसी के वैगन मरम्मत कारखाना और कानपुर के विद्युत लोको शेड एवं ट्रैक्शन मोटर शेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

उ.म.रे. के खिलाड़ी और सांस्कृतिक टीम के कलाकार अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाते रहे हैं. इस अवसर पर महाप्रबंधक ने अपने मुक्केबाजों, जिमनास्टों और जूनियर क्रिकेट टीम को अखिल भारतीय रेल चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर बधाई दी. उ.म.रे. में शांति और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सक्रिय योगदान देने के लिए उन्होंने मान्यताप्राप्त यूनियनों, संघों एवं संगठनों को हार्दिक बधाई दी. विभिन्न सामाजिक कार्यों में सदैव निःस्वार्थ भाव से योगदान देने के लिए स्काउट्स और गाइड्स को भी बधाई दी. महाप्रबंधक ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद रेलकर्मियों और उनके परिजनों की सहायता में सराहनीय योगदान देने के लिए उ.म.रे. महिला कल्याण संगठन को भी मेरी हार्दिक बधाई दी.

पदोन्नति में केवल वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाए -कैट

चंडीगढ़ : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने रेलवे में तकनीकी कैडर के पुनर्गठन में आरक्षित वर्ग को पदोन्नति (प्रमोशन) देने के मामले में आरक्षण को दरकिनार कर केवल वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने का आदेश दिया है. कैट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है. कैट की एक खंडपीठ ने हाल ही में रेलवे के डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स (डीएलएमडब्ल्यू) पटियाला में डीजल टेक्नीशियन ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत 39 कर्मचारियों की ओर से दायर एक याचिका के संबंध में यह फैसला सुनाया है. इन कर्मचारियों ने रेल प्रशासन के उस निर्णय को कैट में चुनौती दी थी, जिसमें कैडर का पुनर्गठन करते हुए एससी/एसटी कोटे के कर्मचारियों को प्रमोशन में लाभ पहुंचाया गया था.

डीएलएमडब्ल्यू पटियाला के कर्मचारी गुरपिंदर सिंह समेत अन्य टेक्नीशियनों ने अपनी इस याचिका में भारत सरकार, सेक्रेटरी/रे. बो. और डीएलएमडब्ल्यू पटियाला के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) को प्रतिवादी बनाया था. याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने वर्ष 1990-92 में डीजल टेक्नीशियन ग्रेड-1 के तौर पर रेलवे में नौकरी शुरू की थी. इसके बाद वह वर्ष 1995 से 2000 के बीच ग्रेड-2 एवं ग्रेड-1 में पदोन्नत प्रमोट हुए थे. अक्तूबर 2013 में रेलवे ने फैसला किया कि 1 नवंबर 2013 को कुछ कैडर का पुनर्गठन किया जाएगा. इसके अनुसार सीनियर टेक्नीशियन के 31 रिक्त पदों को डीजल टेक्नीशियन ग्रेड-1 के रूप में कार्यरत कर्मियों के जरिए भरने का निर्णय लिया गया. परंतु तभी मई 2014 में कैट ने कैडर पुनर्गठन में आरक्षण के माध्यम से रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने पर रोक लगा दी थी. खंडपीठ ने अपने निर्णय में डीएलएमडब्ल्यू पटियाला को आदेश देते हुए कहा कि तकनीकी कैडर के पुनर्गठन में आरक्षण को दरकिनार किया जाए और प्रमोशन में केवल वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाए. साथ ही सभी योग्य ग्रेड-1 टेक्नीशियंस को सीनियर टेक्नीशियंस के ग्रेड के पदों पर समायोजित किया जाए.

संजय यादव पूर्वोत्तर रेलवे के नए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे के नए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) के रूप में संजय यादव ने 13 अगस्त को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. इसके पूर्व वह आप पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, गोरखपुर में ही उप महाप्रबंधक/सामान्य (डीजीएम/जी) के पद पर कार्यरत थे. 3 अप्रैल 1968 को जन्में श्री यादव ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सन 1991 में सिविल इंजीनियरिंग में एम.टेक की उपाधि प्राप्त की थी. श्री यादव 1999 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी हैं. भारतीय रेल में उनकी पहली नियुक्ति वर्ष 2001 में दक्षिण रेलवे के तिरुअनंतपुरम मंडल के अंतर्गत कोल्लम में सहायक मंडल इंजीनियर के पद पर हुई थी. उन्होंने दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल में मंडल इंजीनियर, उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण के पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया है. श्री यादव जनवरी 2007 में दक्षिण रेलवे से स्थानांतरित होकर पूर्वोत्तर रेलवे में आए थे. उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, गोरखपुर में अब तक उप मुख्य इंजीनियर/टीपी, उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण एवं उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/इंजीनियरिंग के पदों पर कार्य करते हुए अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्यालय, गोरखपुर में उप मुख्य राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार को नई ऊंचाई दी है. श्री यादव को रेल प्रबंधन एवं प्रशासन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त है तथा मृदुभाषी होने से वह रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों में काफी लोकप्रिय हैं.

अजीवन सदस्यता 3000 रु.,
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.,
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. : 9869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर्स हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जिला- ठाणे. (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक – सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
- भुसावल : शेख सत्तार ☎ 093706 15244
- रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 094274 84069
- वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 098240 16464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017